वाई-फाई चौपाल से पंजाब के गांव होंगे हाई-फाई

जासं, पटियाला : डिजिटल इंडिया स्कीम के तहत केंद्र सरकार राज्य के सभी गांववासियों को 6 महीने के लिए मुफ्त वाई-फाई सुविधा देने जा रही है। केंद्र ने इस सुविधा को वाईफाई चौपाल के नाम से शुरू किया है। चौपाल का मतलब सत्य से है, जो हर गांव में आम देखने को मिल जाती है। इस स्कीम का प्रमुख उद्देश्य टाउन एरिया व ग्रामीण इलाकों में लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा मुहैया करवाना है। इस सुविधा से ई-गवर्नेंस और डिजिटल डवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। टेलीकॉम कंपनियां देशभर में अपना 4जी नेटवर्क फैला रही हैं। फिर भी कई ऐसे रूरल इलाके हैं, जहां आज भी इंटरनेट नहीं है। इसके लिए राज्य के विभिन्न जिलों में उपकरण पहुंचने शुरू हो चुके हैं। इस साल के अंत तक गांववासियों को सुविधा मिलनी शुरू हो गई जाएगी। **गांव में 400 मीटर तक का एरिया कवर होगा :** इस स्कीम के तहत हर गांव 100 मीटर रेंज वाले 4 वाई-फाई टावर लगाने जा रही है। इससे हर गांव में आबादी के हिसाब से विभिन्न स्थानों पर 4 टावर लगेंगे, जो 400 मीटर एरिया कवर कर वाई-फाई सुविधा देंगे। जिला सूचना अफसर संजीव कुमार शर्मा ने बताया कि वाई-फाई सेवा शुरू करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिये गांव तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाई जा रही है। इसके तहत 1 एमबीपीएस से 1 जीबीपीएस तक इंटरनेट हाई स्पीड मिलेगी।

10 आरोपितों से छह घंटे पूछताछ

एसआइटी के इनपुट के बाद मोगा में पहुंची सीबीआइ टीम ने अलग-अलग की पूछताछ

जागरण संवाददाता, मोगा : बरगाड़ी बेअदबी मामले की जांच सीबीआइ ने शुरू कर दी है। एसआइटी की ओर से मिले इनपुट के बाद सीबीआइ की पांच सदस्यीय टीम रविवार को मोगा पहुंच गई थी। टीम ने सोमवार को सभी 10 आरोपितों से छह घंटे तक अलग-अलग पूछताछ की। सीबीआइ ने एसआइटी की ओर से जुटाए सबूतों के आधार पर सवालों की सूची तैयार की है। सोमवार सुबह आठ बजे ही सीबीआइ की पांच सदस्यीय टीम सीआइए स्टाफ मोगा पहुंच गई। उनके साथ एसएसपी राज जीत सिंह भी मौजूद थे।

बरगाड़ी बेअदबी मामले में एसआइटी ने 10 आरोपित भी संदीप कुमार को कोटकपूरा से गिरफ्तार कर लिया है। संदीप कुमार को भी अदालत में पेश कर एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। गौरतलब है कि एसआइटी की ओर से काबू किए गए सुखजिंदर सन्नी, संदीप नीला, शक्ति सिंह, बलजीत सिंह, निशान सिंह, रंजीत सिंह, महेंद्र पाल, प्रदीप कुमार, नरिंदर शर्मा और संदीप कुमार का काबू किया जा चुका है। आरोपित कबूल कर चुके हैं कि बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी में उनकी संलिप्तता रही है। एसआइटी ने आरोपितों से कुछ मोबाइल नंबर भी पता लगाए थे जिससे मुख्य आरोपित अन्य लोगों को निर्देश देता था।

मोगा सीआइए स्टाफ में बरगाड़ी कांड के आरोपितों से पूछताछ कर बाहर निकलते एसएसपी राज जीत सिंह, डीआइजी रणबीर सिंह खटड़ा और सीबीआइ टीम के सदस्य।

बरगाड़ी कांड

- मामले से जुड़ा दसवां आरोपित भी काबू, एक दिन के रिमांड पर भेजा
- सीबीआइ ने तैयार की सवालों की सूची, एसआइटी की जांच से संतुष्ट

जांच पूरी होने पर बड़े नामों तक पहुंच सकती है इसकी तपिश : डीआइजी एसआइटी के प्रमुख डीआइजी रणबीर सिंह खटड़ा का कहना है कि अभी मामले की जांच चल रही है। जांच पूरी होने के बाद इसकी तपिश बड़े नामी लोगों तक जा सकती है। एसआइटी सीबीआइ को पूरा सहयोग कर रही है। सीबीआइ एसआइटी की अभी तक की जांच से संतुष्ट है।

बलजीत के घर 104 दिन छिपाकर रखा पावन ग्रंथ

राजीव शर्मा ● फरीदकोट

बरगाड़ी बेअदबी के तीनों मामलों की जांच में जुटी एसआइटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सीबीआइ को सौंप दी है। । माना जा रहा है कि 19 जून को सीबीआइ सभी 10 आरोपितों को प्रोडक्शन वारंट पर ले लेगी। फिलहाल सीबीआइ मोगा सीआइए में आरोपितों से पूछताछ कर रही है। वहीं, सीबीआइ ने सोमवार को मोगा व फरीदकोट पुलिस को साथ लेकर फरीदकोट में डेरा प्रेमियो के घर छापामारी की। सीबीआइ ने गांव डग्गो रोमाणा के शक्ति सिंह के घर की भी तलाशी ली। इससे पहले एसआइटी की पड़ताल में सामने आया है कि सिख जत्थेबंदियों द्वारा डेरे की गतिविधियों का लगातार विरोध करने की रंजिश में बरगाड़ी समेत कुछ स्थानों पर बेअदबी की घटनाओं को अंजाम दिया गया।

कब, कहां और कैसे की बेअदबी

साजिश के सूत्रधार महिंदरपाल बिट्टू के कहने पर 1 जून 2015 को गांव बुर्ज जवाहर वाला के गुरुद्वारा साहिब से डेरा

जांच में आया सामने, सिख जत्थेबंदियों की रंजिश में की थी बेअदबी, डग्गो रोमाणा के शक्ति सिंह के घर भी टीम ने दी दबिश

अनुयायी फरीदकोट के रणदीप सिंह नीला और कोटकपूरा के सुखजिंदर सिंह सन्नी कंडा ने पावन स्वरूप चुराकर कोटकपूरा के गांव सिखांवाला में बलजीत सिंह नाम के डेरा प्रेमी के घर छिपा दिया। 24 सितंबर 2015 को बुर्ज जवाहर सिंह वाला के ही गुरुद्वारा साहिब के बाहर अश्लील शब्दावाली वाला पोस्टर लगाया। पोस्टर सुखजिंदर सिंह सन्नी, निशान सिंह व प्रदीप कुमार उर्फ राजू ने चिपकाया था। पोस्टर तैयार करने में कोटकपूरा के संदीप कुमार बिट्टू का हाथ होने का शक है। 12 अक्टूबर 2015 को पावन ग्रंथ के पन्ने फाड़कर उन्हें बरगाड़ी के गुरुद्वारा साहिब के बाहर फेंक दिया। इस घटना में गांव डग्गोरोमाना के शक्ति सिंह, सुखजिंदर सिंह सन्नी व कोटकपूरा के रणजीत सिंह भोला का हाथ था। बाद में खंडित स्वरूप को महिंदरपाल ने कोटकपूरा के सीवरेज ड्रेन में फेंक दिया।

कनाडा में कमलजीत व दूसरे तस्करों के संपर्क में भी था देव

संस, जालंधर : लंगर के बर्तनों में अफीम और केटामाइन ड्रग सप्लाई करने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार हुआ कैनेडियन नागरिक राजस्थान के श्रीगंगानगर निवासी दविंदर देव कनाडा के ड्रग तस्कर कमलजीत सिंह चौहान ही नहीं बल्कि और भी ड्रग तस्करों के संपर्क में था। पुलिस ने देव और उसके साथियों अजीत सिंह, त्रिलोचन सिंह और गुरबख्श सिंह को अदालत में पेशकर चार दिन के रिमांड पर लिया है। रिमांड के दौरान पता चला है कि देव ने दो बार नहीं बल्कि दो से ज्यादा बार ड्रग की खेप कनाडा भेजी। बताया जा रहा है कि कनाडा के अलावा भी कई देशों में देव के साथी मौजूद हैं जो ड्रग्स की खेप मंगवाते थे लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। वहीं जालंधर, राजस्थान, होशियारपुर व अन्य शहरों में भी गिरोह से जुड़े सदस्य हैं। इनके बारे में देव और उसके साथियों से रिमांड के दौरान पूछा जाएगा। देव से ड्रग की सप्लाई लेने वाले कमलजीत सिंह की गिरफ्तारी के लिए भी यहां की पुलिस कनाडा पुलिस से संपर्क साधने की तैयारी में है। इस संबंध में एआइजी काउंटर इंटेलीजेंस हरकंवलप्रीत सिंह खख ने बताया कि रिमांड के दौरान चारों से पूछताछ की जाएगी। यह पता लगाया जाएगा कि इस धंधे में उनके साथ और कौन-कौन जुड़े हुए हैं। उनका कहना था कि पकड़े गए चारों बड़ी उम्र के हैं, इसलिए पूछताछ में थोड़ी परेशानी आ रही है।

खून के घूंट पी सुनानी पड़ती है कोर्ट में आबरू लुटने की कहानी

बाल यौन शोषण अब बस!! #AbBas

27 मार्च 2017 को दो सहेलियां घर से किताबों को जिल्द चढ़वाने के लिए बाजार गई थीं। इनमें एक 13 वर्ष की थी, जबकि दूसरी 17 वर्ष की थी। दोनों वापस नहीं लौटीं। पुलिस की जांच में सामने आया कि कैंट के धोबियाना रोड निवासी अजय उर्फ आकाश और खुशी नाम के दो युवक उन्हें अगवा कर ले गए हैं। दो दिन बाद पुलिस ने दोनों आरोपितों को बस स्टैंड इलाके से गिरफ्तार करके दोनों नाबालिगों को मुक्त करा लिया। मेडिकल में सामने आया कि दोनों से दुष्कर्म किया गया था। थाना कैंट पुलिस ने आरोपित युवकों के खिलाफ अगवा करने और दुष्कर्म के आरोप में केस दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया।

बच्चियों के दुष्कर्म के मामलों में सबसे ज्यादा दिक्कत तब आती है, जब उन्हें अदालत में डिफेंस के सवालों का सामना करना पड़ता है। पीड़िता की पैरवी करने वाले वकील को पहले सारी कहानी अदालत के सामने सुनानी पड़ती है। उसके बाद डिफेंस के वकील पीड़िता से ऐसे सवाल पूछते हैं, जिनके जवाब देने में उन्हें समाज के सामने शर्म महसूस होती है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। पहले ही दिन डिफेंस के सवाल सुन दोनों पीड़िता घबरा गईं। उसके बाद अदालत ने उनका मेडिकल करने वाली महिला डॉक्टर को गवाही के लिए बुलाया। डिफेंस ने डॉक्टर पर भी कई ऐसे सवाल दाग दिए, जिनके जवाब देने में वो असहज नजर आने लगीं।

अदालत के सवाल-जवाब से दोनों नाबालिग बच्चियां निराश हुईं और घबरा गईं, जिस पर मैंने अदालत में हाईकोर्ट की नई डायरेक्शन संबंधी एक याचिका दायर की। इसके तहत पीड़िता व डॉक्टरों के बयान देने के समय अदालत में केवल जज, स्टेनो दोनों पक्ष के वकील और पीड़िता ही रह सकती हैं। अदालत में बैठे अन्य सभी लोगों को बाहर भेज दिया जाता है, ताकि पीड़िता बिना किसी हिचक के अपने जवाब अदालत के सामने रख सके। अदालत ने मेरी याचिका को स्वीकार करते हुए पीड़िताओं के बयान कलमबद्ध किए। हालांकि, इस प्रकार के सवाल पूछने के पीछे डिफेंस का मकसद बच्ची को जलील करना नहीं होता, मगर ऐसा करना उनकी ड्यूटी होती है। न चाहते हुए भी उन्हें वो सवाल पूछने पड़ते हैं।

पीड़िताओं के बयान दर्ज होने के बाद केस गवाहियों पर चला गया था। हर तरफ से घिर चुके आरोपित पक्ष ने केस बंद करने के लिए पीड़ित युवतियों को धमकाना शुरू कर दिया, जिससे दहशत में आए दोनों परिवारों ने पहले पीछे हटने का फैसला कर लिया। मगर जब उन्हें समझाया गया, तो वो सहज हो गए। आरोपितों व उनके शुभचिंतकों के खिलाफ अदालत में एक और याचिका दायर की गई। इसके बाद लगातार आने वाली धमकियों का सिलसिला थम गया। लंबी जद्दोजहद के बाद अब केस फैसले के करीब है। जल्दी ही दोनों आरोपितों को अदालत सजा सुनाएगी।

-रंजीत सिंह जलाल सीनियर एडवोकेट, बठिंडा बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान।

सीएम ने पीएम से की खाद्य कर्ज निपटारे की मांग

सीमावर्ती इलाकों व राष्ट्रीय कृषि ऋण माफी स्कीम के लिए विशेष पैकेज की मांग दोहराई

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर धान व गेहूं की खरीद के लिए 31000 करोड़ रुपये के खाद्य कर्ज के निपटारे का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार द्वारा खातों का निपटारा न किए जाने के कारण 12 हज़ार करोड़ मूल राशि और 19000 करोड़ रुपये ब्याज का बोझ राज्य सरकार के उठाना पड़ रहा है।

इस मुलाकात के दौरान कैप्टन ने कहा कि राज्य पहले ही 324 करोड़ रुपये के सालाना ब्याज का भुगतान कर रहा है। कुल भुगतान 65000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। यह बोझ सहना राज्य के लिए मुश्किल है। सरहदी इलाकों के विकास के लिए विशेष पैकेज की मांग दोहराते हुए कैप्टन ने कहा सीमावर्ती क्षेत्र विकास फंड के आवंटन संबंधी मापदंड पंजाब के हक में नहीं है। इस संबंध में त्रुटियां दूर की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने नवंबर, 2019 में श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाशोत्सव के संबंध में 2145 करोड़ रुपये की सहायता की मांग भी दोहराई। 13 अप्रैल 2019 को जलियांवाला बाग की शौर्यगाथा के 100 वर्ष पूरे होने पर अमृतसर में होने वाले आयोजन और स्थल के आसपास सुविधाओं के लिए सौ करोड़ रुपये का अनुदान देने की अपील की। उल्लेखनीय है कि जलियांवाला बाग ट्रस्ट के चेयरमैन प्रधानमंत्री हैं। किसानों की समस्याओं का जिक्र करते हुए कैप्टन ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 100 प्रतिशत केंद्रीय फंड मुहैया करवाने की मांग दोहराई।

सतलुज, व्यास का मुद्दा उठाया : मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से गंगा कार्य योजना की तर्ज पर सतलुज व ब्यास नदियों की सफ़ाई के प्रोजेक्ट के लिए सहायता की मांग की।

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की ● प्रेट्र

राहुल को गिफ्ट किया केक

चंडीगढ़: कैप्टन अमरिंदर सिंह सोमवार को पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी से मिले और उन्होंने राहुल को जन्म दिन की बधाई देते हुए केक गिफ्ट किया। यह मुलाकात विशुद्ध रूप से जन्म दिन की बधाई को लेकर थी। करीब ढाई मिनट की मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री के साथ पार्टी की पंजाब प्रभारी आशा कुमारी भी साथ में थी। बता दें कि मंगलवार को राहुल गांधी का जन्म दिन है।

शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट को शीघ्र मिले मंजूरी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शाहपुर-कंडी डैम प्रोजेक्ट की जल्द मंजूरी दिए जाने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने इस प्रोजेक्ट को 90:10 के अनुपात को कायम रखने और प्राथमिकता दिए जाने की अपील की है। कैप्टन ने यह मुद्दा सोमवार को दोपहर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ एक मीटिंग के दौरान उठाया। कैप्टन ने सरहिंद फीडर और राजस्थान फीडर नहर प्रोजेक्टों की जल्द मंजूरी की मांग करते हुए गडकरी से पीएमकेएसवाई के अंतर्गत इन दोनों प्रोजेक्टों के लिए केंद्रीय फंड उपलब्ध करवाने के लिए कहा है। शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट को शीघ्र शुरू करने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्र से अपील की कि वह 31 मार्च, 2017 के समझौते को आगे ले जाने के लिए जम्मू-कशमीर सरकार को कहे। यह समझौता 90:10 के नियमों के अनुसार मंजूर हुआ है जबकि अब 60:40 का प्रस्ताव किया जा रहा है।

पंथक व किसानों के मुद्दे पर दबाव बनाएगा अकाली दल

रणनीति

- सुखबीर के नेतृत्व में केंद्रीय गृहमंत्री से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल
- पीड़ितों के लिए इंसाफ व स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कराने की मांग

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : लंबे समय से लटकते आ रहे पंथक और किसानों के मुद्दों को केंद्र सरकार के पास से हल कराने के लिए अकाली दल ने केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति बनाई है। पंथक मुद्दों में ऑपरेशन ब्लू स्टार के से संबंधित गुप्त दस्तावेज़ रिलीज करना, अपनी सज़ाएं पूरी करन के बाद देश की अलग -अलग जेलों में बंद सिख कैदियों की रिहाई, 84 के सिख विरोधी दंगों के दोषियों को सज़ा दिलाना शामिल है।

पंथक एजंडे साथ-साथ अकाली दल ने अपना किसानी वोट बैंक बचाने के लिए मोदी सरकार पर स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए दबाव बनाने का भी एजेंडा बनाया है। उक्त मुद्दों को लेकर पार्टी ने फ़ैसला किया है कि पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में शिष्टमंडल केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को मिलेगा और भारत सरकार को सिखों और किसानी के मसले जल्द से जल्द हल कराने की अपील करेगा। सोमवार को हुई बैठक में केंद्र सरकार से पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कम करने की मांग पर भी चर्चा हुई। सुखबीर बादल ने कहा कि हम सिखों और किसानी के अहम मसलों को ल कर इसी हफ़्ते गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मिलेंगे। आज की मीटिंग में अकाली के सरप्रस्त प्रकाश सिंह बादल, एसजीपीसी के प्रधान गोबिंद सिंह लोंगोवाल, रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा, सुखदेव सिंह ढींडसा, बलविंदर सिंह भूंदड़, जत्थेदार तोता सिंह, महेश इंदर सिंह ग्रेवाल, बिक्रम सिंह मजीठिया, दलजीत सिंह चीमा, प्रेम सिंह चन्दूमाजरा, सिकन्दर सिंह मलूका और शरणजीत सिंह ढिल्लों शामिल थे।

बिना ईवे बिल के माल भेजने वाली 6 कंपनियों पर दबिश

जासं, लुधियाना : स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स मोबाइल विंग बिना ईवे बिल के मटीरियल भेजने वालों पर शिकंजा कस रहा है। हाल ही में विभाग ने लुधियाना में पंद्रह ट्रकों को एक साथ बिना ईवे बिल के पकड़ा था। । सोमवार को मंडी गोबिंदगढ़ और खन्ना की छह कंपनियों पर कार्रवाई की। विभाग ने ट्रकों में लदे सरिये और लोहे का मार्का देखकर मंडी गोबिंदगढ़ की पांच और खन्ना की एक फर्म पर दबिश दी। एडिशनल ईटीसी (इनवेस्टीगेशन) कुमार सौरव के दिशा निर्देश में हुई कार्रवाई में 100 लोगों की टीम ने सभी फर्मों पर एक साथ दबिश दी। वर्धमान आदर्श इस्पात प्राइवेट लिमिटेड में एईटीसी मोबाइल विंग मंगेश सेठी, समाना इस्पात प्राइवेट लिमिटेड में एईटीसी मोबाइल विंग बठिंडा ने, बाबा स्टील इंडस्ट्री में एईटीसी विजय गर्ग मोबाइल विंग फतेहगढ़ साहिब, फ्रेंड्स इंडस्ट्री में शरणजीत सिंह एईटीसी मोबाइल विंग फतेहगढ़ साहिब, झंडू स्टील एंड एग्रो इंडस्ट्री में वीएस भंगू एईटीसी मोबाइल विंग पटियाला और भारत इस्पात में पीएस सेखों ज्वाइंट डायरेक्टर बठिंडा ने जांच की।

एम्स की प्रवेश परीक्षा में भी छाई ब्लैकबेल्ट अदिति, देश में 17वां रैंक

जासं, हिसार : एम्स की ओर से सोमवार को जारी प्रवेश परीक्षा के परिणाम में शहर की बेटी अदिति ने देशभर में 17वां रैंक हासिल किया है। सेक्टर 13 निवासी अदिति शर्मा ने इससे पहले सीबीएसई द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (नीट) में देशभर में 37वां रैंक हासिल किया था। कराटे में ब्लैकबेल्ट अदिति का कहना है कि डाक्टर बनना उनका लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह उसके लक्ष्य की एक सीढ़ी है। उसका मकसद है इंसानी शरीर के बारे में जानना। शरीर के हर छोटे से छोटे और अंतिम अंग तक उसे जानना है। अदिति के अनुसार इंटरनेट आपको घर बैठे सब कुछ सिखा सकता है। उसका सही इस्तेमाल जरूरी है। उसने इंटरनेट का उपयोग कर कुरियन भाषा सीखी। अब कुरियन पॉप सुनती है। अदिति के पिता पवन शर्मा सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में मैनेजर व मां बबीता शर्मा गृहिणी हैं।

अदिति शर्मा।

वाट्सएप-फेसबुक नो मोर, सेल्फ स्टडी पर जोर

जागरण टीम, पटियाला/बठिंडा : एम्स एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा में देश में टॉप करने वाली संगरूर जिले के लहरागागा की एलिजा ने पटियाला में अपनी सफलता के राज भी शेयर किए। एलिजा ने बताया कि वह दो साल से घर से दूर पटियाला में पीजी में रहकर पढ़ाई कर रही थी। इस दौरान उसने न टीवी देखा न सोशल मीडिया को ऑपरेट किया। हर रोज पांच से छह घंटे कमरे में पढ़ाई की। एलिजा ने रोज 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी की। कोई सवाल हुआ तो उसी समय शिक्षकों से बात कर उसे क्लीयर किया। दो साल से मोबाइल में न वाट्सएप न फेसबुक इंस्टाल किया। स्टडी में इंटरनेट ने बहुत मदद की। कुछ समझ में न आए तो इंटरनेट का सहारा लिया। एलिजा इससे पहले केवीपीवाइ की परीक्षा में टॉप और नीट में 196वां रैंक हासिल कर चुकी है।

घर पर पढ़ाई, सोशल मीडिया से दूरी से पाया मुकाम : एम्स एमबीबीएस परीक्षा में दूसरे स्थान पर रहने वाली बठिंडा शहर की रमनीक कौर माहल ने बताया कि उसकी सफलता का राज घर पर पांच से छह घंटे स्टडी नहीं होगी को सफलता नहीं मिलती। रमनीक के माता-पिता दोनों डॉक्टर हैं उनसे भी बहुत मदद मिली। इससे पहले रमनीक ने नीट में देश में दसवां और प्रदेश में तीसरा रैंक हासिल किया था। रमनीक का भाई हरजिंदर सिंह माहल भी सीबीएसइ दसवीं में जिले में टॉपर था। रमनीक ने बताया कि वे न्यूरो सर्जन बनना चाहती है।

एम्स एंट्रेंस टेस्ट में देश भर में प्रथम स्थान हासिल करने वाली एलिजा को उनकी माता रेणु बाला गोद में उठाकर ● विजय शर्मा। **बेटी पर मान...** एम्स की परीक्षा में देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली बठिंडा की रमनीक कौर को उसकी मां डा. बरिंदर कौर माहल दुलार करती ● रणधीर बॉबी

एम्स एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा की टॉपर्स ने बताया सफलता का राज, एलिजा ने दो साल तक घर से दूर पटियाला में पीजी में रहकर की पढ़ाई

गुड न्यूज चार साल पहले बनाए कर्नाटक एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन ने अपना रंग दिखाना शुरू

कर्नाटक मॉडल से घटेंगी किसान आत्महत्याएं

इन्द्रप्रीत सिंह ● चंडीगढ़

पंजाब सरकार यदि कृषि में कर्नाटक सरकार का मॉडल अपनाए, तो यहां किसान आत्महत्या की घटनाओं में कमी आ सकती है। आत्महत्या में कमी लाने और उन्हें उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लिए चार साल पहले बनाए गए कर्नाटक एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले चार वर्षों में किसानों पर कर्ज का तनाव कम हुआ है। यह दावा है देश के एकमात्र स्टेट एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के चेयरमैन डॉ. टीएन प्रकाश का। वे दो दिन तक चंडीगढ़ में चली डायलॉग हाईवे की नेशनल कांफ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए आए थे। दैनिक जागरण ने उनसे किसानों में बढ़ रही आत्महत्या की प्रवृत्ति और उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर विस्तृत चर्चा की।

डॉ. प्रकाश ने बताया कि कर्नाटक सरकार ने इस ओर कदम उठाया है। किसानों को समय पर उनकी फसलों का उचित मूल्य न मिलने से ही उन पर कर्ज का बोझ बढ़ता है। फिर इस कर्ज को उतारने की चिंता में ही वह आत्महत्या जैसा कदम उठाते हैं। डॉ. प्रकाश ने बताया कि कर्नाटक सरकार ने 2014 में स्टेट प्राइस कमीशन का गठन किया था। इसमें हम फसलों की कीमत सुनिश्चित करते हैं और अगर खुले बाजार में कीमत उससे नीचे जाती है, तो फसल की खरीद सरकार करती है। इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है और पूरे राज्य के किसानों को इस पोर्टल के जरिए फसल की कीमत बताई जाती है, ताकि वे इससे नीचे न बेचें। कमीशन के चेयरमैन ने बताया कि रौंगी, ज्वार, तुअर की दाल, सुपारी, धान समेत दस फसलें हैं, जिनकी कीमत राज्य सरकार तय करती है और कीमत गिरने पर अपनी कीमत पर उसकी खरीद करती है। उन्होंने बताया कि इस सारी खरीदी गई फसलों को राज्य सरकार की विभिन्न स्कीमों के तहत विभागों को बेच दिया जाता है, जिससे सरकार पर इसका बोझ नहीं पड़ता।

डॉ. टीएन प्रकाश।

यह है मॉडल

डॉ. प्रकाश ने बताया कि जेलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, मिड-डे-मील सहित तमाम सरकारी संस्थानों में बनने वाले खाने में राज्य सरकार की ओर से खरीदे गए खाद्यान्न का इस्तेमाल किया जाता है। मार्केट में जैसे ही सरकार फसलों की खरीद शुरू करती, वैसे ही व्यापारी अपना दाम बढ़ा देते हैं और किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम मिलने लगता है। आखिर इसके लिए पैसा कहां से आता है? इसके जवाब में उन्होंने बताया कि एपीएमसी एक्ट के अधीन 1.5 फीसद सैस मंडियों में बिकने वाली फसल पर लगाया है, जिससे सरकार को 1500 करोड़ रुपये से ज्यादा की आमदनी होती है। इस राशि को इसी गैप फंडिंग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

बाजार में व्यापारियों का नेक्सस नहीं बनता

डॉ. प्रकाश ने कहा कि राज्यों के लिए यह फॉर्मूला बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे बाजार में व्यापारियों पर नेक्सस न बनाने का दबाव बना रहता है। उन्हें मालूम है कि अगर सरकार ने खरीद कर ली, तो उसे तय दाम से ज्यादा ही अदा करने होंगे। प्रसिद्ध एग्रो अर्थशास्त्री दविंदर शर्मा ने भी डॉ. प्रकाश के इस दावे की वकालत की है कि अगर सरकार पंजाब में धान के अलावा वैकल्पिक फसलों को गैप फंडिंग देना शुरू कर दे, तो धान का रकबा कम होने लगेगा। खुद सरकार की अपनी आटा-दाल योजना में सरकार को दालों की जरूरत है। इन्हें प्रमोट करके सरकार खरीद करके इस योजना को चलाए। इसी तरह जेलों में भी दालों की जरूरत होती है।